Page Three

Classified

Adds can be booked under these Categories : (all day publication)

Recruitment
Property
Business Opportunity
Vehicles
Announcements
Antiques & Collectables
Barter
Books
Computers
Domain Names
Education
Miscellaneous
Entertainment & Event
Hobbies & Interests
Services
Jewellery & Watches
Music
Obituary
Pets & Animals
Retail
Sales & Bargains
Health & Sports
Travel

Matrimonial (Sunday Only)

अब मात्र रु. 20 प्रति शब्द

सीएम ने टाटा ग्रुप को राज्य के विकास में सहभागिता के लिए किया आमंत्रित

भेंट

टाटा सन्स के चैयरमैन सहित टाटा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम त्रिवेन्द्र से की भेंट

टाटा ग्रुप ने उत्तराखण्ड में आतिथ्य, ऊर्जा और इलेक्ट्रीक वाहन क्षेत्र में निवेश की इच्छा जताई

उद्योगपति सीएम से मुलाकात के दौरान।

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने एन. चंद्रशेखरन चौयरमैन, टाटा सन्स और बनमाली अग्रवाल, अध्यक्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड एयरोस्पेस–टाटा सन्स, से भेंट कर राज्य के विकास में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के लिए राज्य सरकार ने बहुत से महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। मुख्यमंत्री ने टाटा के प्रतिनिधिमण्डल को उत्तराखण्ड आकर विशेष तौर पर पर्यटन, ऊर्जा व विनिर्माण में निवेश की असीमित सम्भावनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया।

उत्तराखण्ड सरकार व टाटा ग्रुप के अधिकारियों ने उत्तराखण्ड में निवेश की सम्भावनाओं पर गहन विचार–विमर्श किया। टाटा ग्रुप और उत्तराखण्ड सरकार के अधिकारियों ने बैठक में राज्य में निवेश की सम्भावनाओं पर विस्तार से चर्चा की। राज्य सरकार के अधिकारियों ने पर्यटन, ऊर्जा, इलेक्ट्रीक वाहन और सूचना प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए।

व्यापक विचार विमर्श के बाद, टाटा ग्रुप ने उत्तराखण्ड के सभी जिलों में एएमए(होम स्टे), ताज (रिसोर्ट), जिंजर (बिजनेस होटल), जीवा (स्पा) आदि ब्राण्ड के माध्यम से आतिथ्य क्षेत्र में काम करने की रूचि जाहिर की। टाटा ग्रुप ने गोआ में फोर्ट अगुआडा और अंडमान निकोबार में हेवलॉक की तर्ज पर पर्यटन के लिए टिहरी झील के विकास की इच्छा जताई। टीसीएस आईओएन, राज्य में स्किलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर विकसित करेगी।

टाटा पावर ने माइक्रो ग्रिड सोल्युशन के माध्यम से विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार में सहयोग के लिए प्रस्ताव दिया ताकि उत्तराखण्ड वर्ष 2023 तक नवीकरणीय ऊर्जा से 50 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया जा सके। टाटा पावर राज्य में सोलर पम्प विनिर्माण में सम्भावनाओं को भी देखेगी। भारत सरकार की फेम–2 योजना का उपयोग करते हुए उत्तराखण्ड में इलेक्ट्रोनिक व्हीकल सेक्टर के विकास पर भी गहन चर्चा की गई। टाटा एडवांस सिस्टम (टाटा ग्रुप की डिफेंस सेक्टर कम्पनी) राज्य में ड्रोन टेस्टिंग का एक्सीलेंस सेंटर विकसित करने में सहभागिता की सम्भावना पर काम करेगी।

बैठक में टाटा ग्रुप की ओर से बनमाली अग्रवाल (अध्यक्ष, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस एंड एयरोस्पेस–टाटा सन्स), वी.रामास्वामी (ग्लोबल हेड–टीसीएस ईओएन), पुनित चटवाल (सीईओ, इंडियन होटल्स), श्री राकेश सिंह (प्रमुख, रिन्युएबल्स बीडी–टाटा पावर), गिरीश वाघ (अध्यक्ष, वाणिज्यिक वाहन बीयू–टाटा मोटर्स) जबकि उत्तराखण्ड सरकार की ओर से श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव, उद्योग, दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन, राधिका झा, सचिव, ऊर्जा, अमित सिन्हा, निदेशक आईटीडीए उपस्थित थे।

न्यूज डायरी

मौसम विभाग की चेतावनी पर डीएम ने घोषित की स्कूलों में छुट्टी

संवाददाता हरिद्वार। उत्तराखण्ड में इन दिनों शीतलहर चल रही है, जिसके कारण लोगों को ठण्ड का अहसास होने लगा है। बर्फबारी और बारिश के बाद गिरे तापमान और शीतलहर के कारण कंपकंपी का एहसास हो रहा है। राज्य मौसम विज्ञान केंद्र ने 20, 21 और 22 दिसंबर को 2500 फीट से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है। जिसको देखते हुए मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के चलते जिलाधिकारी हरिद्वार दीपेन्द्र चौधरी द्वारा 20 दिसंबर को कक्षा 01 से 12 तक के सभी शासकीय अशासकीय विद्यालयों, आँगनबाड़ी केन्द्रों में अवकाश घोषित किया है। साथ ही मुख्य शिक्षाधिकारी को इसे सख्ती से लागु कराने को भी कहा है।

बर्फ के आगोश में उत्तरकाशी का हर्षिल, सिर्फ दो बच्चों ने दी परीक्षा

संवाददाता उत्तरकाशी। हर्षिल घाटी ने इन दिनों बर्फ की चादर ओढ़ी हुई है। इसका सबसे अधिक प्रभाव नौनिहालों की शिक्षा पर पड़ रहा है। बर्फबारी के कारण घाटी में प्राथमिक स्कूल तो हफ्तेभर से बंद हैं, लेकिन एकमात्र इंटर कॉलेज में बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्थिति यह है कि बच्चे मासिक परीक्षाएं देने भी नहीं पहुंच पाए। बुधवार को 65 में से केवल दो बच्चों ने ही परीक्षा दी। इनमें एक छात्र और एक छात्रा शामिल थे। जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से 75 किमी दूर और समुद्रतल से 2650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हर्षिल इन दिनों दो से तीन फिट तक बर्फ जमी हुई है। ऐसे में लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। घाटी के गांवों को बाजार से जोडने वाले रास्ते भी बर्फ से अटे हुए हैं।

बांग्लादेश का प्रतिनिधिमण्डल नियोजन प्रक्रिया के अध्ययन को दून पहुंचा

संवाददाता देहरादून। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कार्यालय, बांग्लादेश योजना आयोग व यूएनडीपी बांग्लादेश के वरिष्ठ सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल, उत्तराखण्ड राज्य की नियोजन प्रक्रिया व क्रियान्विति में सतत विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के समेकन का अध्ययन करने एक दिन के दौरे पर बुधवार को देहरादून पहुंचा। दल के सदस्यों में मुख्य रूप से जनरल इकोनोमिक डिवीजन, बांग्लादेश प्लानिंग कमीशन के प्रमुख मोहम्मद मफीदुल इस्लाम, सदस्य शमसुल आलम व प्रधानमंत्री कार्यालय में सतत विकास लक्ष्य मामलों के अपर सचिव मोहम्मद मुकाम्मल हुसैन शामिल थे। इसी के तहत दल ने उत्तराखण्ड का भी भ्रमण किया।

विंटरलाइन कार्निवाल आयोजन के सम्बन्ध में अधिकारियों संग बैठक करते समिति के उपाध्यक्ष मसूरी विधायक गणेश जोशी।

मसूरी विंटरलाइन कार्निवाल 25 से 30 तक, विधायक ने तैयारियों को लेकर ली बैठक

संवाददाता देहरादून। 25 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक मसूरी के विभिन्न स्थानों में आयोजित होने वाले विंटरलाइन कार्निवाल के सफल आयोजन के सम्बन्ध में मसूरी महोत्सव समिति के उपाध्यक्ष व मसूरी से विधायक गणेश जोशी ने अधिकारियों संग बैठक की। उन्होनें कहा कि पहाड़ो की रानी मसूरी आने वाले किसी भी पर्यटक को कोई असुविधा न हो, इसे प्राथमिकता पर लिया जाए।

बालाहिसार स्थित अपने आवास पर अधिकारियों को निर्देशित करते हुए विधायक जोशी कहा कि पार्किंग के सुलभ इंतजात, यातायात प्रबंध, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल एवं विद्युत की उपलब्धता, बढ़ती ठड़ के चलते अलाव व्यवस्था एवं सफाई व्यवस्था को भी नियमित रुप से देखें। उन्होनें कहा कि प्लास्टिक का प्रयोग न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाए। विधायक जोशी ने बताया कि 25 दिसम्बर को मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा गांधी चौक में 108 फीट ऊँचे झण्डे का लोकार्पण किया जाऐगा। साथ ही मैथोडिस्ट चर्च में फसाड़ लाईटें लगाने का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाऐगा। उन्होनें कहा कि भिलाडू खेल मैदान का कार्य भी जल्द प्रारम्भ किया जाऐगा।

उत्तराखड की गंभीर समस्या है पलायन : कृषि मंत्री

संवाददाता

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की समस्या पर चिन्तन

देहरादून। गुरूवार को सचिवालय स्थित वीर चंद सिंह गढ़वाली सभागार में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद तथा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की उपस्थिति में प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन की समस्या पर चिन्तन विषयक बैठक सम्पन्न हुई।

सदस्य नीति आयोग रमेश चंद द्वारा उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों से पलायन पर चिन्ता व्यक्त करते हुए विशेषकर अभाव के कारण हो रहे पलायन को रोकने के लिए कारगर रणनीति बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सीमान्त क्षेत्र में जनसंख्या निर्वात (क्मउवहतंचीपब अंबननउ) नहीं होना चाहिये क्योंकि ये आबाद गांव सच्चे ''सीमा प्रहरी'' का कार्य करते हैं। राज्य में कृषि के प्रति घटते रूझान पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उन्होंने सुझाव दिया गया कि ''लैण्ड लीजिंग'' कानून में परिवर्तन करके कान्ट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना होगा ताकि परती जमीन का उपयोग हो सके।

पर्वतीय क्षेत्रों में सेटेलाइट सिटीज को विकसित करने का सुझाव भी दिया गया। उन्होंने समान परिस्थिति के पड़ोसी हिमाचल राज्य की रणनीति का भी अनुभव शामिल करने का अधिकारियों को सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के सीमान्त क्षेत्रों से पलायन होना चिन्ता का विषय है। पलायन से गांव में रह रहे अन्य लोगों में भी असुरक्षा का वातावरण होता है जिससे गांव के अस्तित्व को भी खतरा हो जाता है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि विकास के साथ साथ पलायन सभी राज्यों में हुआ है, परन्तु उत्तराखण्ड सीमान्त क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण यहां गांव खाली होना चिन्ता की बात है। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड की 90 प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है तथा भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहां विभिन्न योजनाओं में संचालित अवस्थापना निर्माण कार्यों में लागत अधिक आती है। पलायन यहां की गंभीर समस्या है, इसीलिए भारत सरकार से हिमालयी राज्यों हेतु पृथक नीति बनाने का आग्रह किया गया तथा आपदा के मानकों को भौगोलिक स्थिति के अनुरूप सुसंगत करने का अनुरोध किया गया।

नागरिकता कानून धर्म के आधार पर घुसपैठियों को नागरिकता देने वाला काला कानून

संवाददाता देहरादून। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 धर्म के आधार पर अवैध घुसपैठियों को उनकी भारत में घुसपैठ की तिथि से नागरिकता के लिये प्रावधान करने वाला काला कानून है। यह असंवैधानिक व मूल अधिकार हनन करने वाला कानून भारत की सर्वधर्म समभाव की विश्व छवि को खराब तो करेगा ही साथ ही विदेशों में हिन्दुओं पर अत्याचार बढ़ाने वाला हिन्दू विरोधी कानून भी है।

उक्त उदगार प्रतिष्ठित समाज सेवी संस्था मौलाना अबुल कलाम आजाद अल्पसंख्यक कल्याण समिति (माकाक्स) के केन्द्रीय अध्यक्ष तथा कानून के जानकर नदीम उद्दीन (एडवोकेट) ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके प्रभावों पर जानकारी देते हुये व्यक्त किये। नदीम ने बताया कि 6 धाराओं के इस कानून में धारा 2 से अवैध प्रवासी जिसे साधारण शब्दों में अवैध घुसपैठिया कहा जा सकता है, की परिभाषा में स्पष्ट किया है कि 31 दिसम्बर 2014 से पूर्व भारत में प्रवेश करने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान के हिन्दू, सिक्ख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के व्यक्तियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जायेगा।